1	2	3
11.	Importing Country Responses for chemicals included in the PIC procedure—status	Background Paper 7.
12.	Draft disclaimer and cover pages for future DGDs	Background Paper 8
13.	Candidates Chemicals for possible inclusion in the PIC procedure	Background Paper 9.
	* with 5 or more valid control actions	
	* with control actions entering into force after 1 January, 1992	
	* chemicals no longer in production, but still being traded	
14.	Technical matters related to Category 1A+ pesticides verbal presentations and discussion of additional information	
15.	Review of draft DGDs	Background Paper 10
16.	Final decision on inclusion of chemicals in PIC closed session	
	* chemicals with valid control actions	
	* chemicals included because of problems in developing countries (Category 1A+	
17.	Other matters	
18.	Adoption of report	

Model watershed projects

4424. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the National Watershed Development Policy Committee has approved Model Watershed Projects for all the 115 selected Agro Climatic zones;

(b) how many such zones are in Maharashtra;

(c) whether all the 2,410 Watershed Development Projects to be taken up by the States have been approved;

(d) if not, what are the reasons therefor;

(e) how many of them are in Maharashtra; and

(f) what are the salient features of the criterion laid down for the approval of (a) and (c) above?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Out of 115 selected Agro-climatic Zones, the National Watershed Development Policy Committee has approved Model Watershed Plans for 107 Agro-climatic Zones. In addition 7 more Model Projects have been finalised and technical clearance given to State Governments. One Model Watershed is pending with Karnataka Government.

(b) The National Watershed Development Project for Rainfed Areas (NWDPRA) is in operation in 9 Agro-climatic Zones in Maharashtra and all the 9 Model Watersheds have been cleared by Government of India.

(c) and (d) The State Governments have formulated 2067 projects and the State Level Sanctioning Committees of various States have sanctioned 1921 watershed projects. Formulation of the remaining watershed projects is in progress.

(e) In Maharashtra 266 Watershed projects have been sanctioned by the State Level Sanctioning Committee

(f) In accordance with the Project Guidelines one Model Watershed in each of the Agro-climatic Zones is finalised by Government of India in consultation with the officials of the State Governments, which are then put up for consideration and approval of National Watershed Development Policy Committee.

Based on the Approved Model Watershed Projects, the State Level Sanctioning Committee approves the other Watersheds projects.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उपलब्धियां

4425. **श्री कामेश्वर पासवान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पिछले दो वर्षों की क्या उपलब्धियां हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान पर किया गया खर्च कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि देने में असफल रहा है;

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन प्रकाशन और सूचना प्रभाग स्थापित किये जाने के क्या उद्देश्य है और यह अपने उद्देश्य में कितना सफल रहा है ;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण अनुसंधान कार्य में भारी गिरावट आयी है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि प्रकाशन प्रभाग की पत्रिकायें इसके पाठकों को तीन-चार महीने बाद मिल पाती हैं; और

(च) यदि हां, तो इन प्रकाशनों के अत्यधिक विलंब से आने के क्या कारण हैं?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) विभिन्न फसलों के अधिक उपज देने वाली किस्मों/संकरों को रिलीज किया गया/पता लगाया गया । इससे खाद्यान्न की 192, तिहलनों की 74, दलहनी फसलों की 21, व्यावसायिक फसलों की 30 और चारे वाली फसलों की 16 किस्में/संकर शामिल हैं । आगे ब्यौरा विवरण के रूप में दिया जा रहा है । **(नीचे देखिये)**

(ख) जी, नहीं । यह तथ्य नहीं है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बारानी और सिंचित पारिस्थितियों दोनों स्थितियों के लिये अधिक उपज देने वाली, खाद्यान्न, दहलनी, तिलहनी और बागवानी फसलों की अधिक उपज देने वाली तैयार की गयी किस्मों के रूप में महत्वपूर्ण परिणाम दिखाये ।

(ग) प्रकाशन एवं सूचना प्रभाग की स्थापना भा0कृ0अ0प0 के इस कार्यदेश का पालन करने के लिये हुई थी जिसमें "परिषद को न केवल अनुसंधान बल्कि सामाय रूप से कृषि और पशु चिकित्सा संबंधी मामलों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं के क्लीयरिंग हाउस (सूचना प्राप्त करना व वितरित करना) के रूप में कार्य करना है । प्रभाग प्रारंभ से ही अंग्रजी और हिन्दी में नियमित रूप से पत्रिकायें और विभिन्न अंगों पर 1000 से अधिक गैर-आवधिक प्रकाशन प्रकाशित करके काफी हद तक इस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है । इनमें से कुछ प्रकाशनों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है और इनसे परिषद को काफी ख्याति मिली है । प्रभाग ने एफ.ए.ओ. और साक के स्तर पर राष्ट्रीय सूचना में भी अंशदान दिया है और अन्तर्राष्ट्रीय सूचना-तंत्रों जैसे एग्रिस, सी.ए.आर.आई.एस. और एस.ए.आई.सी को समृद्ध किया है ।